नवभारत (पटना) 7 दिस. 1984

भोपाल कारखाने के मालिक 'हर्जाने' से बचना चाहते हैं

—आलोक मेहता—

नई दिल्ली, ६ दिसम्बर। पता चला है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी के इकाई अमरीका भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस के शिकार लोगों को अमरीकी मानदंडों और ९ अरब डालर की वार्षिक बिक्री या १० अरब डालर की संपत्ति के आधार पर हर्जाना देने के 'मूड' में नहीं है। वे भोपाल के कारखाने के 'शेड' में भवन के साथ या तथाकथित 'उचित सहायता का मुआवजा' देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं।

केन्द्रीय रसायन मंत्री श्री वसंत साठे और मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह अमरीकी दूतों से ही हर्जाना दिए जाने की मांग कर चुके हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि हर्जाने का फैसला अदालत में हो।

दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना से शिकार अमरीका की ५०० प्रमुख बड़ी कम्पनियों में सैंतीसवें स्थान पर रहने वाली यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एम. एंडरसन ने एक अमरीकी पत्रिका 'फोर्बस' को एक इन्टरव्यू में कहा था कि 'धंधा' करने वाले जो लोग बुरी खबर सुनकर घबराते या डरते हैं।

इनका धंधा चौपट होने लगता है। शायद इसी मानसिकता के कारण इस कम्पनी के भारतीय साझेदारों और प्रबन्धकों ने भी जहरीली गैस के उत्पादन में कमी लाना महसूस नहीं किया और दो दुर्घटनाएं होने के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इन्तजाम नहीं किए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रबन्धक भारत में हुई दुर्घटना को 'केवल एक कारखाने' की दुर्घटना मानकर उसी कारखाने की क्षमता के अनुरूप हर्जाना देने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उसकी साझेदार भारतीय कम्पनी ने भी १९८३ में ९ अरब १९ करोड़ रुपए का धंधा किया है। कर देने से पहले उसका मुनाफा करीब १५ करोड़ रु. रहा है। १९८१ में उसकी शेयर पूंजी ३३ करोड़ ५८ लाख रु. और २१ करोड़ ६१ लाख की कुल जायदाद संपत्ति रही है।

५० वर्ष से चल रही यह भारतीय कम्पनी 'एवरेडी' के नाम से १९ तरह की बैटरियां बनाकर सबसे अधिक मुनाफा कमा रही है। इसके अलावा यह २१ प्रकार की प्लास्टिकवाइड और डार्क तैयार करती है और उसके बनाए कार्बन ड्रेस के करीब दस हजार सिलेंडरों में उपयोग किए जाते हैं। कम्पनी की बैटरियां भारतीय सेना की बड़ी मात्रा में ली जाती हैं।

इस कम्पनी ने भारत की आजादी निर्यात करने के लिए देश में बिकने वाले 'लिटरेचर' की ५० प्रतिशत की जिम्मेदारी ली हुई है। बहरहाल लगता है कि इसके एक कारखाने में जहरीली गैस के लीक होने की कम करने का कम्पनी का बोझ भी कुछ हल्का कर दिया है।

इस संवाददाता द्वारा भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों से बातचीत करने पर यह तथ्य भी सामने आया है कि अमेरिका या पश्चिमी देश में कोई भी कम्पनी अपनी किसी इकाई में हुई दुर्घटना के लिए सामूहिक रूप से हर्जाना देने से नहीं बच सकती है। न ही वह असावधानी के लिए कुछ कर्मचारियों पर सारी जिम्मेदारी डाल कर सीधापीछा कर सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार यूनियन कार्बाइड कम्पनी के पास करीब चार अरब डालर (करीब ४८ अरब रु.) की राशि 'इक्विटी पूंजी' के रूप में जमा है और वह इसका उपयोग हर्जाना देने के लिए कर सकती है। कम्पनी के दुनिया भर में ५०० कारखाने हैं, जिनमें एक लाख सोलह हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसीलिए भारत में अधिकतम हर्जाना देने में उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। अमेरिका में तो कई बार एक ही दुर्घटना, जबकि किसी कारखाने की दुर्घटना या प्रदूषण से हुई मौतों के लिए बड़ी संख्या में लोगों को कम से कम दस-दस लाख डालर का हर्जाना दिया गया है। इसलिए भारतीयों को हर्जाना देने के लिए जनमत भी बनाना होगा।